संख्या:8/2020/27एनए(18)/35-आ0-1-2017-28-टीसी-5

प्रेषक,

आमोद कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग-1, नियोजन विभाग
द्वितीय तल, योजना भवन

लखनऊ:दिनांक:27 जुलाई,2020

विषय: प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 से सभी विभागों द्वारा सृजित एवं सार्वजनिक उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों की जियो टैगिंग कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से सभी कार्यक्रम/योजना/परियोजना के नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण को जियो इंफार्मेटिक्स सिस्टम आधारित प्रणाली के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य योजना आयोग-1 नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:1/2018/27एनए(18)/35-आ0-1/2017-28, दिनांक:17 जुलाई, 2018 की प्रति संलग्न है।

2- उक्त कार्य हेतु समन्वय एवं अनुश्रवण का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

3- रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0, लखनऊ को प्रदेश के कतिपय प्राधिकरणों यथा- बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरणों से जियो स्पेशियल तकनीक आधारित कार्यादेश प्राप्त है जिसमें बरेली, मुरादाबाद, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरणों के लिए खसरा मानचित्रों का जियो रिफरेन्स कर मोजैक बनाते हुए मास्टर प्लान के साथ सुपर इम्पोज करते हुए जियो स्पेशियल डेटाबेस तैयार किये गये हैं, जिससे प्रत्येक खसरा में प्रस्तावित भू-उपयोग को ज्ञात किया जा सके। उक्त कार्य से भविष्य की योजनाओं के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी।

4- रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0, लखनऊ ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वर्तमान में तैयार की गयी कॉलोनी के जियो इंफारमेशन सिस्टम आधारित डेटाबेस के माध्यम से प्रत्येक प्लॉट के एलाटमेन्ट एवं अन्य सूचनाओं को एक क्लिक से ज्ञात किया जा सकता है। यह सूचना भी प्राप्त की जा सकती है कि प्राधिकरण की कॉलोनी में अभी तक खाली प्लॉटों की स्थिति क्या है और कॉलोनियों में अन्य सुविधाओं/इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी चिन्हित करते हुए रिमोट सेंसिंग द्वारा मैप तैयार किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- जियो स्पेशियल तकनीकी से यदि आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उ0प्र0 लखनऊ के वैज्ञानिक श्री आलोक कुमार सैनी जिनका मोबाइल नम्बर:9839912030 है, से सम्पर्क स्थापित कर कार्य का भुगतान नियमानुसार वर्कआर्डर के माध्यम से कराया जा सकता है। रिमोट एप्लीकेशन्स सेन्टर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था है एवं उक्त कार्यों के लिए शासन द्वारा नामित नोडल एजेन्सी भी है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आमोद कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या:8/2020/27एनए(18)/35-आ0-1-2017-28-टीसी-5, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, नियोजन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5- आवास आयुक्त उ0प्र0, आवास एवं विकास परिषद,
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- कार्यवाहक निदेशक, रिमोट सेंसिंग एप्लकेशन्स सेन्टर, जानकीपुरम कुर्सी रोड, लखनऊ।

(आमोद कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।